the development of infrastructure facilities with a view to exploiting their existing potential and sustaining their contribution to the national economy.

(c) Yes, Sir. The State Governments of Maharashtra, Tamil Nadu and UP are represented in the Task Force.

(d) According to the notification issued by the Planning Commission, the Task force is expected to submit its final report by the end of December, 1995.

(e) and (f) Yes, Sir. The 10th Finance Commission has recommended an amount of Rs. 1000 crores as grants to local bodies to be made available to the State Governments in four equal instalments commencing from 1996-97.

उत्तर प्रदेश को विश्व बैंक सहायता

1252. श्री संघ प्रिय गौतम: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार ने किन-किन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त की है और इस प्रयोजना के लिए कितनी धनराशि मिली है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस सहायता से पूरे किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) राष्ट्रीय कृषि विकास परियाजना के नाम से कोई परियोजना नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-3 1987 से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में चल रही थी। इसके अतिरिक्त, 1991 से यह परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में चल रही थी। पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कवर किए गए जिलों के नाम संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं (नीचे देखिए) इस परियोजना की अवधि 31 मार्च, 1995 की पूरी हो गई।

गत 3 वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए प्राप्त राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(लाख रुपये में)

	1992-93	1993-94	1994-95
1754-आईएन राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना II	1027.95	1838.67	2651.95

(ख) लक्ष्यों की तुलना में विश्व बैंक सहायता से पूरे किए गए कार्य का अद्यतन ब्यौरा संलगन विवरण-2 में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) जी, हां।

(घ) निम्नलिखित तालिका में 1986-87 अर्थात् परियोजना शुरू होने की अवधि से पूर्व और 1993-94; वह अवधि जब परियोजना अभी चल रही थी, में कृषि उत्पादन की तुलनात्मक स्थिति अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार दी गई है:-

(हजार मीटरी टन)

क्र० सं०	मद	1986-87	1993-94
1.	चावल	7509.3	10115.3
2.	गेहूं	16235.9	20797.7
3.	कुल अनाज	27621.5	34480.6
4.	कुल खाद्यान्न	30249.4	36968.9

स्रोत:- (1) वर्ष 1986-87 के लिए

"भारत में प्रमुख फसलों के क्षेत्र, और उत्पादन (1990-93)" 77वां अंक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित।

(2) वर्ष 1993-94 के लिए

"1993-94 के लिए खाद्यान्नों के क्षेत्र और उत्पादन के अनुमानों का राज्य वार सारांश अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित।

विवरण

एन०ए०ई०पी०-3 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कवर किए गए जिलों के नाम

	पूर्वी उत्तर प्रदेश		पश्चिमी उत्तर प्रदेश
1.	लखनऊ	1.	बिजनौर
2.	राय बरेली	2.	फतेहपुर
3.	फैजाबाद	3.	आगरा
4.	सुलतानपुर	4.	फिरोजाबाद
5.	वारानसी	5.	मैनपुरी
6.	जौनपुर	6.	मथुरा
7.	देवरिया	7.	एटा
8.	आजमगढ़	8.	अलीगढ़
9.	लखीमपुर	9.	बरेली
10.	बहराइच	10.	शांहजहांपुर
11.	प्रताप गढ़	11.	पिलीभीत
12.	गोरखपुर	12.	बदायूं
13.	बस्ती	13.	झांसी
14.	बलिया	14.	ललितपुर
15.	गाजीपुर	15.	जालौन
16.	हरदोई	16.	हमीरपुर
17.	सीतापुर	17.	महोबा
18.	गौंडा	18.	बांदा
19.	बाराबंकी	19.	कानपुर
20.	मिर्जापुर	20.	कानपुर (ग्रामीण)
21.	सोनभद्रा	21.	फरूखाबाद
22.	उन्नाव	22.	इटावा
23.	महाराज गंज	23.	मेरठ
24.	मऊ	24.	गाजियाबाद
25.	सिद्धार्थ नगर	25.	सहारनपुर
		26.	मुज्जफर नगर
		27.	बुलन्दशहर
		28.	हरिद्वार
		29.	मुरादाबाद
		30.	रामपुर

विवरण-II

लक्ष्यों की तुलना में किए गए कार्य का ब्यौरा

	इन्क्रीमेंटल स्टाफ की स्थिति		सिविल कार्य		वाहन		प्रशिक्षण कार्यक्रम	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
उत्तर प्रदेश (पूर्वी जिले) एन० ए०ई०पी०-III	5566	3938	1956	1030	158	148	15470	21579
उत्तर प्रदेश (पश्चिमी जिले)*	4216	3293	1489	1172	231	201	21357	7668

*- यह परियोजना एन.ए.ई.पी.-I और III के अंतर्गत वित्त पोषित की गई।

Contribution for Natural Calamities

1253. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the present ratio of contribution of the Central and State Governments in cases of natural calamities;

(b) whether Government of Orissa has submitted a proposal for the ratio as 90:10; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) to (c) According to the Report of the Tenth Finance Commission, the Government of Orissa had suggested to the Commission, reduction in the State share of the Calamity Relief Fund (CRF) from 25 percent to 10 percent. The Commission has, however, recommended continuance of the scheme already in vogue and did not consider it necessary to change the pattern of Centre-State contributions to the CRF, which is in the ratio of 3:1 Government of India have accepted the recommendations of the Commission.

Central Government Employees' Welfare Housing Organisation

1254. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT to be pleased to state: